RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह




वर्ष : 17 अंक : 25 प्रति सोमवार, 9 नवंबर 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

### देवास टीआई दिलीप पुरी की मौत ने फिर खड़े किए गंभीर सवाल

# मप्र की कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर हमला, कानून को चुनौती



कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में खाकी वर्दी एक बार फिर निशाने पर है। जिस वर्दी के कंधों पर प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व है, जब उसी वर्दी को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देवास जिले के खातेगांव में थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत ने एक बार फिर प्रदेश में सक्रिय अवैध कारोबार और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। यह केवल एक पुलिस अधिकारी की मौत नहीं, बल्कि कानून के सामने खड़ी उस चुनौती का संकेत है, जिसमें अवैध कारोबार से जुड़े लोग कार्यवाई रोकने के लिए जानलेवा कदम




पुलिसकर्मियों की मौत और शहडोल में एएसआई महेंद्र बागरी की जान जाना ऐसे मामले हैं, जिन्होंने समय-समय पर व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। 2012 से अब तक अवैध खनन और शराब परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सात सरकारी कर्मचारियों की जान गई, जिनमें चार पुलिसकर्मी शामिल थे। इन घटनाओं को महज अलग-अलग आपराधिक वारदात मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर राज्य सरकार इनके पीछे छिपे नेटवर्क, आर्थिक हितों और स्थानीय स्तर पर मिलने वाले संभावित संरक्षण की जांच करने में अब तक क्यों विफल साबित हो रही है। सवाल यह है कि जब किसी इलाके में अवैध कारोबार लगातार फलता-फूलता है तो क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं होती? यदि जानकारी होती है तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती? और यदि कार्रवाई होती है तो उसे अंजाम देने वाले अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? (शेष पेज 2 पर)

### 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

## मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विजन में गांव, गरीब, किसान और युवा होंगे विकास के केंद्र



-विजया पाठक

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय का वर्ष 2047 के लिए विजन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांवों की आत्मनिर्भरता, किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं का सशक्तीकरण, आदिवासी अंचलों का विकास, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य और आधुनिक अधोसंरचना को समान महत्व दिया गया है। इस सोच का मूल आधार है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक पहचान तथा मानवीय संसाधनों के बल पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। मुख्यमंत्री के विजन में विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर ऐसे राज्य की है, जहां विकास के अवसर केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहें। बस्तर से सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों से वनांचलों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हो। राज्य की भौगोलिक विविधता को चुनौती के बजाय विकास की ताकत बनाया जाए। इसके लिए क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इस विजन को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत वर्ष 2030 तक अल्पकालिक लक्ष्य, 2035 तक मध्यम अवधि के लक्ष्य और 2047 तक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। (शेष पेज 2 पर)

## वोट बचाओ, देश बचाओ रैली: राहुल गांधी ने भरी सियासी हुंकार

-विजया पाठक

दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को आयोजित विपक्षी गठबंधन इंडिया की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित इस रैली का केंद्रीय मुद्दा भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, मतदाता सूची की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संविधान की रक्षा रहा। विपक्ष ने इस मंच के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इसे किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी जनआंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। रामलीला मैदान का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। देश के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों ने इसी मैदान से कई बार सत्ता के सामने अपनी आवाज बुलंद की है।



(शेष पेज 3 पर)

3



"मिस मध्य प्रदेश"- सागर की बेटी डॉ. गरिमा गोस्वामी

5



समाजवादी राजनीति की नई पीढ़ी का चेहरा

7



हर साल की भांति इस बार भी दिल्ली मे जहरीली हवा

# मुख्यमंत्री साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसान कल्याण को दी नई गति

(पेज 1 का शेष)

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विजन दस्तावेज केवल घोषणाओं का संकलन नहीं, बल्कि समयबद्ध कार्ययोजना है। इसे तैयार करने में किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और विभिन्न वर्गों के लोगों के सुझाव भी शामिल किए गए हैं।



## अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

विकसित छत्तीसगढ़ के विजन में अर्थव्यवस्था का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपये और 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए खनिज आधारित अर्थव्यवस्था के साथ विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना है। छत्तीसगढ़ पहले से ही इस्पात, सीमेंट, बिजली और खनिज उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब सरकार इन पारंपरिक क्षेत्रों के साथ नए उद्योगों को जोड़कर अर्थव्यवस्था को विविधता देना चाहती है। औद्योगिक नीति 2024-30 के माध्यम से फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर जोर है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य को आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चुनौती इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर उद्योग, उत्पादन और रोजगार में बदलने की होगी।

## किसानों की आय और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर

छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। इसलिए विजन 2047 में खेती को लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने को प्रमुख स्थान दिया गया है। कृषि उन्नति मिशन, आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को विकसित करने की दिशा में काम करने की रूपरेखा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसान केवल कच्चे कृषि उत्पादों के उत्पादक बनकर न रहें, बल्कि प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन से भी जुड़ें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। धान उत्पादन के लिए पहचान रखने वाले छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, उद्यानिकी और अन्य वैकल्पिक फसलों की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना इस रणनीति का हिस्सा है। विजन दस्तावेज में 2047 तक किसानों की आय में दस गुना से अधिक वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

## वन संपदा बनेगी रोजगार और समृद्धि का आधार

छत्तीसगढ़ की पहचान उसके घने जंगलों, जैव विविधता और वनोपज से भी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य की लघु वनोपज को केवल संग्रहण तक सीमित रखने के बजाय उसके प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन से ग्रामीण एवं आदिवासी परिवारों की आय बढ़ाई जा सकती है। तेंदूपत्ता, इमली, महुआ, साल बीज और अन्य वन उत्पादों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां विकसित करने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।इस दिशा में महिला स्व-सहायता समूहों, वन समितियों और स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। सरकार की मंशा है कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी प्राकृतिक संपदा का बेहतर आर्थिक लाभ मिले। इससे पलायन कम करने और गांवों में आजीविका के स्थायी साधन विकसित करने में भी मदद मिल सकती है।

## आदिवासी अंचलों में विकास के साथ सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण

विजन 2047 में बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी पूरा होगा, जब राज्य के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार की समान सुविधाएं मिलेंगी। बस्तर में शांति और सुरक्षा की बेहतर होती स्थिति को विकास के नए अवसरों से जोड़ने की योजना है। सरकार की प्राथमिकता है कि वहां केवल सड़क और भवन निर्माण ही न हो, बल्कि स्कूल, अस्पताल, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, बाजार और रोजगार के साधन भी विकसित हों। नियद नेल्लानार जैसी पहलों और बस्तर के अंदरूनी गांवों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों को इसी व्यापक सोच से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर भी है कि बस्तर का विकास उसकी स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए हो। जनजातीय कला, लोकनृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान को विकास की प्रक्रिया से जोड़ना इस क्षेत्र को नई पहचान दे सकता है।

## महिलाओं और युवाओं को मुख्यधारा में लाना

मुख्यमंत्री के विजन में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता मिल रही है। इसके साथ ही 13.85 लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनने की उपलब्धि का उल्लेख भी किया गया है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें उद्यमी और आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करने वाली शक्ति बनाना है। महिला स्व-सहायता समूहों को उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और छोटे उद्योगों से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगारपरक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर है। मुख्यमंत्री ने कौशल प्रशिक्षण को प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के सहयोग से नई दिशा देने की बात कही है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश से उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है।

## पर्यटन, तकनीक और अधोसंरचना से बदलेगी राज्य की तस्वीर

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। चित्रकोट जलप्रपात, बस्तर के वन क्षेत्र, सरगुजा के प्राकृतिक स्थल और राज्य की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन के बड़े केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है। इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार और कारोबार के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही सड़क, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था से उद्योगों को कच्चा माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी। रायपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भी अवसर विकसित करने की बात विजन दस्तावेज में शामिल है। डिजिटल प्रशासन को भी विकास का आधार बनाया जा रहा है। ई-ऑफिस प्रणाली, सरकारी खरीद में जेम पोर्टल और योजनाओं की निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल जैसे उपायों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचे।

## लक्ष्य बड़ा, चुनौती उसे जमीन पर उतारने की

मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय का विजन 2047 छत्तीसगढ़ को संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर आधुनिक, समावेशी और अवसरों से भरपूर राज्य बनाने की महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें उद्योग और कृषि के विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तीकरण, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को भी स्थान दिया गया है। हालांकि, इस विजन की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि घोषित लक्ष्यों के अनुरूप निवेश कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है, युवाओं को कितने रोजगार मिलते हैं, किसानों की आय में कितनी वास्तविक वृद्धि होती है और दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं किस गति से पहुंचती हैं। 2047 अभी दूर है, लेकिन उसकी तैयारी आज के फैसलों और योजनाओं से ही होगी। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदा, मेहनतकश जनता और नई तकनीक के समन्वय से विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

# मप्र की कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर हमला, कानून को चुनौती

(पेज 1 का शेष)

## माफिया का दुस्साहस या व्यवस्था की कमजोरी?

प्रदेश में कभी रेत माफिया की गतिविधियां चर्चा में रहती हैं तो कभी अवैध खनन, शराब तस्करी और शिक्षा के नाम पर चल रहे संगठित कारोबार की शिकायतें सामने आती हैं। स्कूलों में मनमानी फीस और नियमों के उल्लंघन के आरोप हों या खदानों में अवैध उत्खनन का मामला, हर जगह प्रशासन की जिम्मेदारी का सवाल उठता है। लेकिन परिणाम कुछ नहीं सामने आते, समस्या जस की तस बनी हुई है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब बनती है जब किसी अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारी को ही अपनी जान गंवानी पड़ जाए। आखिर अपराधियों के मन में कानून का भय इतना कमजोर कैसे पड़ जाता है कि वे पुलिस की मौजूदगी में भी कानून को चुनौती देने का दुस्साहस कर लेते हैं? क्या केवल कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? जब तक अवैध कारोबार की आर्थिक जड़ों और उसके पूरे नेटवर्क पर चोट नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का खतरा बना रहेगा।

## मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जवाबदेही के सवाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिस बल की सुरक्षा को लेकर उनकी जवाबदेही और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही है, लेकिन जमीन पर इसका प्रभाव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। माफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। मरने-मारने का भय माफियाओं के दिमाग से निकल गया है।

## कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा मामला?

मध्यप्रदेश में कानून का राज केवल सरकारी घोषणाओं और पुलिस की वर्दी से कायम नहीं होता। इसके लिए अपराधियों के मन में कानून का भय और जनता के मन में सुरक्षा का विश्वास होना जरूरी है। पुलिसकर्मी जब किसी तस्कर को रोकने के लिए सड़क पर उतरता है तो उसके पीछे शासन और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की ताकत होनी चाहिए। यदि वह अकेला पड़ जाता है तो यह केवल पुलिस विभाग की नहीं, बल्कि शासन की विफलता है। मोहन सरकार को यह भरोसा देना होगा कि ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को अपराधियों के सामने असहाय नहीं छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर देवास के टीआई दिलीप पुरी की मौत को एक और घटना बनाकर भुला देना सबसे बड़ी भूल होगी। यह मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने खड़ा बड़ा प्रश्न है, जिसका जवाब माफियाओं पर कार्यवाही कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करके देना होगा।

# "मिस मध्य प्रदेश" का ताज पहनकर सागर की बेटी डॉ. गरिमा गोस्वामी ने बढ़ाया मान



-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर के आभासी कक्ष में "मिस मध्य प्रदेश" का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर सागर का गौरव बढ़ाने वाली शहर की प्रतिभावान बेटी डॉ. गरिमा गोस्वामी के आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गुप्ता ने की, जबकि मंच पर प्रशासनिक अधिकारी डॉ. इमराना सिद्दीकी की गरिमामयी उपस्थिति रही। महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉ. गरिमा गोस्वामी को फूल-मालाओं, पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉ. गरिमा गोस्वामी की इस शानदार उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि संपूर्ण महाविद्यालय परिवार और पूरे सागर संभाग ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. सरोज गुप्ता ने डॉ. गरिमा गोस्वामी की इस बड़ी उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि कड़ी प्रतियोगी दौर में होने वाली इस प्रतियोगिता में सिर्फ चेहरे और रंग-रूप का सौंदर्य नहीं, बल्कि बौद्धिकता और व्यक्तित्व का सौंदर्य भी परखा जाता है। जिसमें डॉ. गरिमा ने अपना परचम लहराते हुए इस शिखर को छुआ है। ऊपरी सौंदर्य के बजाय आंतरिक सौंदर्य से परिपूर्ण व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस तरह की प्रतियोगिताओं में भी वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सागर और प्रदेश का नाम देशभर में रोशन करेंगी।" अग्रणी महाविद्यालय में अपने स्वागत और सम्मान से अभिभूत डॉ. गरिमा गोस्वामी ने सभी का आभार ज्ञापित करते हुए सौंदर्य प्रतियोगिता के विभिन्न चरण तथा इसकी चुनौतियों को साझा कर कहा कि किसी भी व्यक्ति को चेहरे से सुंदर होना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके दिल में प्रेम दया करुणा और सबसे बड़ी बात सफलता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प व आत्मविश्वास भी होना उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस पूरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे माता-पिता और परिवार जनों का है जिन्होंने हर कदम पर मुझे प्रोत्साहित करने का काम किया और मैंने सफलता हासिल की। प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वह बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें लगातार प्रोत्साहन दें और उनका उत्साह बढ़ाते रहें तो निश्चित रूप से उन्हें भी हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ संदीप सबलोक ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सागर के अतिरिक्त संचालक डॉ. रामकुमार गोस्वामी की सुपुत्री डॉ गरिमा गोस्वामी ने अपने शैक्षिक जीवन में हमेशा ही प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नीट की बेहद कठिन और चुनौती पूर्ण परीक्षा पास करते हुए वर्तमान में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर रही है। उनकी माताजी श्रीमती आशा गोस्वामी बीएसएनएल में अनुविभागीय इंजीनियर अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

# वोट बचाओ, देश बचाओ रैली: राहुल गांधी ने भरी सियासी हुंकार

(पेज 1 का शेष)

भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से लेकर बड़े राजनीतिक संघर्षों तक, इस मैदान ने भारतीय लोकतंत्र के कई महत्वपूर्ण अध्याय देखे हैं। ऐसे में यहां आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली केवल एक राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि विपक्ष की ओर से जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश भी थी कि लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता और नागरिक के मताधिकार का महत्व सर्वोपरि है। राहुल गांधी ने इस रैली के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया। उनका जोर इस बात पर रहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है और यदि मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, तो उनका पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए।

## वोट चोरी का मुद्दा बना विपक्ष की लड़ाई का केंद्र

इस रैली की सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर उठे विवाद में छिपी है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूचियों में संशोधन के नाम पर बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि इस प्रक्रिया से गरीब, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और कमजोर सामाजिक वर्ग के मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम शामिल होना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। यदि किसी नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी सीधा असर पड़ता है। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे पर्याप्त सूचना और अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितने नाम हटाए गए, किन कारणों से हटाए गए और कितने लोगों ने दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता केवल राजनीतिक दलों की मांग नहीं, बल्कि हर मतदाता का अधिकार है। हालांकि, चुनाव आयोग और सरकार का पक्ष भी इस बहस में महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण फर्जी, दोहरे और अपात्र नामों को हटाने तथा सूची को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। आयोग के अनुसार, गलत तरीके से नाम हटने की स्थिति में नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकते हैं। इसलिए एसआईआर को लेकर उठे सवालों का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि आंकड़ों, दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच से होना चाहिए। राहुल गांधी और विपक्ष की मांग है कि इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा हो और मतदाता सूची से जुड़े हर फैसले का स्पष्ट हिसाब जनता के सामने रखा जाए। लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होती, बल्कि यह जनता की राजनीतिक भागीदारी का आधार है। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि या पक्षपात की आशंका को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

## विपक्षी एकजुटता ने दिखाई नई राजनीतिक तस्वीर

इस रैली का एक बड़ा राजनीतिक पक्ष विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता भी रहा। पिछले कुछ समय से गठबंधन के भीतर कई राज्यों में सीटों के बंटवारे, नेतृत्व और राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में रामलीला मैदान पर एक साझा मंच पर विपक्षी नेताओं का जुटना अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम था।

रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सहित कई प्रमुख विपक्षी नेता मौजूद रहे। इन नेताओं ने अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद मतदाता सूची और चुनावी निष्पक्षता के सवाल पर एक साझा मंच तैयार किया। ममता बनर्जी का इस मंच पर सोनिया गांधी को अपना नेता कहकर संबोधित करना भी राजनीतिक दृष्टि से चर्चा का विषय बना। यह संकेत था कि विपक्षी दल अपने आपसी मतभेदों को पीछे रखकर कम से कम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और मतदाता अधिकारों का मुद्दा उठाया, जबकि तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र की लड़ाई को व्यापक राजनीतिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी अपने संबोधनों में संविधान, नागरिक अधिकार और देश की एकता का सवाल उठाया। यह एकजुटता कितनी टिकाऊ होगी, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह केवल विरोध के मंच तक सीमित न रहे। उसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी साझा कार्यक्रम बनाना होगा। केवल चुनाव आयोग या केंद्र सरकार के विरोध में एकत्रित होने से जनता का स्थायी विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। जनता को यह भी जानना है कि यदि विपक्ष को शासन का अवसर मिलता है तो वह देश की व्यवस्था को किस तरह बेहतर बनाएगा।

## चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है। यह संस्था केवल चुनाव कराने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता की संवैधानिक संरक्षक भी है। देश में चुनाव तभी निष्पक्ष माने जा सकते हैं, जब सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं को यह विश्वास हो कि चुनाव आयोग बिना किसी दबाव या पक्षपात के काम कर रहा है। रामलीला मैदान की रैली में विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को रोकने और हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग भी की गई। विपक्ष ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्थान पर बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को भी दोहराया।

# Gen Z युवा प्रांजल जैसे कलाकार राज्य की लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की मजबूत कड़ी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला, संस्कृति और पारंपरिक विधाओं को सहेजने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समर्पित रायपुर के युवा लोककलाकार प्रांजल सिंह राजपूत के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का एक स्नेहिल पत्र असीम प्रेरणा और खुशियों की सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रांजल की कला साधना, शिक्षा और भरथरी लोकगायन के संरक्षण-संवर्धन के प्रयासों की सराहना किए जाने के बाद से युवा कलाकार बेहद गदगद और भावुक हैं।

## मुख्यमंत्री के पत्र में लोककला साधना की सराहना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने पत्र में प्रांजल सिंह की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उल्लेख किया है कि उन्होंने भौतिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद लोकसंगीत की विभिन्न विधाओं को जीवंत रखा है। श्रीमती रेखा जलक्षत्री के मार्गदर्शन में भरथरी सीखने की उनकी यह कला यात्रा अब अन्य नवोदित साधकों तक भी पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि प्रांजल अपनी भरथरी प्रस्तुतियों में गायन के साथ-साथ अभिनय और नृत्य को भी बखूबी स्थान देते हैं। इसके साथ ही, उन्होंने 'अहिल्या गाथा' की शानदार प्रस्तुति के जरिए लोकविधाओं में कई नए और रचनात्मक प्रयोग किए हैं।

## नई पीढ़ी को निःशुल्क दे रहे हैं प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री साय ने युवा कलाकार द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रांजल 'लोकगाथा भरथरी' के माध्यम से नए कलाकारों को पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा, 'आकार' शिविर के जरिए बच्चों से लेकर वरिष्ठजनों तक को अपनी कला का ज्ञान बांट रहे हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षित कलाकार आज विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां देकर इस सांस्कृतिक थाती को आगे बढ़ा रहे हैं।

## प्रधानमंत्री के आह्वान और Gen Z पीढ़ी की भूमिका

अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की प्राचीन लोकपरंपराओं और कथावाचन की विविध शैलियों को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित करने के आह्वान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भरथरी सीखने और सिखाने का प्रांजल का यह सत्प्रयास इसी राष्ट्रीय भावना से मजबूती से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रांजल सिंह को Gen Z पीढ़ी के उन होनहार युवाओं में शुमार किया, जिनके कंधों पर छत्तीसगढ़ की लोककलाओं की आगे की गौरवशाली यात्रा टिकी हुई है।

## सम्पादकीय

# ट्रंप मिडटर्म में हारे, अमेरिकी राजनीति में बदलेगा सत्ता का समीकरण

अमेरिका की राजनीति में तीन नवंबर 2026 को हुए मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। इन चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। यह परिणाम महज कुछ सीटों का उलटफेर नहीं, बल्कि ट्रंप की कार्यशैली, नीतियों और नेतृत्व के प्रति अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी का स्पष्ट संकेत है। राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के बाद जिस आत्मविश्वास के साथ ट्रंप ने अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया था, मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने उस राजनीतिक आत्मविश्वास को चुनौती दे दी है। अमेरिकी लोकतंत्र की खूबी यही है कि वहां राष्ट्रपति की लोकप्रियता और उसकी पार्टी का चुनावी प्रदर्शन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में जनता को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इस बार मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता के दोनों सदनों में बहुमत से दूर कर दिया। इसका सीधा अर्थ है कि ट्रंप के लिए अब अपने राजनीतिक एजेंडे को संसद से मंजूरी दिलाना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिकी नागरिकों की आर्थिक परेशानियां रहीं। महंगाई, रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, जीवनयापन की लागत और आर्थिक अनिश्चितता ने मतदाताओं के फैसले को प्रभावित किया। ट्रंप ने अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने और रोजगार बढ़ाने के बड़े वादे किए थे। लेकिन आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहे दबाव ने इन वादों की राजनीतिक चमक को फीका कर दिया। चुनाव परिणाम बताते हैं कि मतदाता केवल बड़े नारों और आक्रामक राजनीतिक भाषणों से संतुष्ट नहीं होते, वे अपने जीवन में वास्तविक बदलाव चाहते हैं। ट्रंप की व्यापार नीति और आयात शुल्क लगाने की रणनीति भी सवालों के घेरे में रही। उनका मानना रहा है कि दूसरे देशों से आयात पर शुल्क बढ़ाने से अमेरिकी उद्योगों को लाभ मिलेगा और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन व्यापारिक शुल्कों का प्रभाव अंततः उपभोक्ताओं और कारोबार पर भी पड़ता है। महंगी वस्तुओं और बढ़ती आर्थिक लागत के बीच आम अमेरिकी नागरिकों ने सरकार की नीतियों का हिसाब मतदान के माध्यम से दिया है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान के साथ युद्ध और उससे जुड़े आर्थिक प्रभावों ने भी चुनावी माहौल को प्रभावित किया। ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक अस्थिरता को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी। अमेरिकी मतदाताओं का एक वर्ग यह सवाल उठाता रहा कि विदेशों में सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेप की कीमत आखिरकार अमेरिकी नागरिक क्यों चुकाएं? इस असंतोष ने रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया।



## सियासी गहमागहमी

### मध्यप्रदेश भाजपा कार्यालय मंत्री के नाम पर मुहर

मध्यप्रदेश भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों का मामला एक बार फिर खींचतान का कारण बनता दिखाई दे रहा है। कार्यालय मंत्री के रूप में डाक्टर निशांत खरे के नाम पर मुहर लगने के साथ ही पार्टी के भीतर राजनीतिक समीकरणों और दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। संगठन में पद हासिल करना अब केवल जिम्मेदारी का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और गुटीय संतुलन का भी सवाल बनता जा रहा है। भाजपा का दावा हमेशा अनुशासित और कार्यकर्ता आधारित संगठन का रहा है, लेकिन नियुक्तियों के समय सामने आने वाली नाराजगी और असंतोष कई सवाल खड़े करती है। आखिर संगठन में जिम्मेदारी तय करने का आधार अनुभव, सक्रियता और कार्यक्षमता है या फिर नेताओं की पसंद और राजनीतिक समीकरण? कार्यालय मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद संगठन की कार्यप्रणाली से जुड़ा होता है, इसलिए इस पर होने वाली खींचतान पार्टी की अंदरूनी स्थिति को भी उजागर करती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक सवाल यह भी है कि आखिर संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों को लेकर इतनी खींचतान क्यों होती है? प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ. निशांत खरे को प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। यह नियुक्ति कार्यालय के संगठनात्मक संचालन से जुड़ी है। इसे प्रदेश कार्यालय मंत्री के मौजूदा पद से अलग समझना होगा। भाजपा के लिए असली चुनौती अब नियुक्ति के बाद संगठन में सामंजस्य बनाए रखने की है। क्योंकि पद भले एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उससे जुड़ी अपेक्षाएं पूरे संगठन की होती हैं। सवाल यह नहीं कि किसे जिम्मेदारी मिली, बल्कि यह है कि क्या नियुक्ति के बाद असंतुष्ट खेमों को साथ लेकर चला जा सकेगा? संगठन में अनुशासन की असली परीक्षा आदेश जारी होने के बाद ही शुरू होती है।

### जीतू पटवारी को दिल्ली हाईकमान की फटकार

मध्यप्रदेश कांग्रेस की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हाईकमान की नाराजगी और फटकार की चर्चा ने प्रदेश संगठन के भीतर हलचल बढ़ा दी है। यदि केंद्रीय नेतृत्व ने पटवारी को संगठनात्मक कामकाज और नेताओं के साथ तालमेल को लेकर सख्त संदेश दिया है, तो यह उनके लिए महज चेतावनी नहीं, बल्कि नेतृत्व की कार्यशैली पर उठता सवाल भी है। प्रदेश कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी, आपसी खींचतान और नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी से जूझ रही है। वरिष्ठ नेताओं की अलग-अलग बयानबाजी और संगठनात्मक फैसलों पर असहमति कई बार सार्वजनिक मंच तक पहुंच चुकी है। ऐसे माहौल में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल भाजपा सरकार पर हमला बोलने तक सीमित नहीं रह सकती। उन्हें सभी धड़ों को साथ लेकर चलने और कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने की चुनौती भी निभानी होगी। दिल्ली का सख्त रुख इस बात का संकेत माना जा सकता है कि हाईकमान अब प्रदेश संगठन के प्रदर्शन को लेकर गंभीर है। पटवारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने की है। आखिरकार कांग्रेस को बयानबाजी नहीं, मजबूत संगठन और चुनावी नतीजे चाहिए।

## हफ्ते का कार्टून




## ट्वीट-ट्वीट

E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!
मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई। 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज्यादा एथेनॉल
मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है।
नुकसान किसका? आपका।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

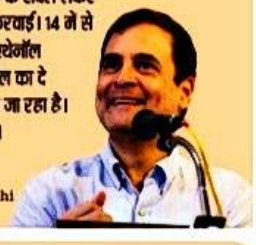

आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनायें। मैं आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सम्पदा की कामना करता हूँ।
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे और हमारा प्रदेश अँधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़े।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath



## राजवीरों की बात

# समाजवादी राजनीति की नई पीढ़ी का चेहरा अखिलेश यादव

**समता पाठक**/जगत प्रवाह



*भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनकी पहचान विरासत से शुरू होकर अपने राजनीतिक संघर्ष, कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता के कारण अलग मुकाम हासिल करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसा ही एक नाम हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने युवा नेतृत्व, विकास, सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा को नए अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनके पिता मुलायम सिंह यादव देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं में रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। राजनीतिक वातावरण में बचपन बिताने के बावजूद अखिलेश की प्रारंभिक शिक्षा और जीवन का अनुशासन उन्हें एक अलग दिशा में ले गया।*

*उन्होंने राजस्थान के धौलपुर सैनिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय से सिविल एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वे ऑस्ट्रेलिया गए और सिडनी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तकनीकी शिक्षा और आधुनिक दृष्टिकोण ने उनके व्यक्तित्व को एक अलग आयाम दिया। अखिलेश यादव ने वर्ष 2000 में कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार संसद में प्रवेश किया। इसके बाद वर्ष 2004 और 2009 में भी वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। संसद में उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति, शहरी विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण से संबंधित समितियों में काम किया।राजनीति में उनकी सक्रियता के साथ युवा कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ती गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन में युवाओं को जोड़ने और पार्टी की राजनीतिक शैली को आधुनिक स्वरूप देने पर जोर दिया। वर्ष 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष थी। वे उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने।*

*मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में आधारभूत संरचना, सड़क, परिवहन, शहरी विकास और तकनीकी सुविधाओं से जुड़े कई कार्यक्रम चर्चा में रहे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे उनकी सरकार की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल रहा। लखनऊ मेट्रो परियोजना की शुरुआत, विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण और समाजवादी एंबुलेंस सेवा जैसी योजनाएं भी उनके कार्यकाल की पहचान बनीं। उनकी सरकार ने विकास के साथ सामाजिक कल्याण की योजनाओं को भी प्राथमिकता देने का प्रयास किया। हालांकि उनके कार्यकाल को लेकर कानून व्यवस्था, प्रशासनिक चुनौतियों और राजनीतिक मतभेदों पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। वर्ष 2017 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन था। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर हुए घटनाक्रम के बाद उन्होंने संगठन की कमान संभाली और नई पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका मजबूत की। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता नहीं मिली, लेकिन अखिलेश यादव ने विपक्ष में रहते हुए अपनी राजनीतिक सक्रियता जारी रखी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वे आजमगढ़ से सांसद चुने गए। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वे विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्नौज से जीत दर्ज कर पांचवीं बार लोकसभा में प्रवेश किया।*

# "स्पंदन–2026" का सांस्कृतिक संध्या के साथ समापन

**-संतोष सिंह कुशवाह**

**जगत प्रवाह. ग्वालियर।** प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान, ग्वालियर के चार दिवसीय वार्षिक महोत्सव "स्पंदन–2026" का समापन 4 नवंबर को जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सभागार में आयोजित सांस्कृतिक संध्या एवं समापन समारोह के साथ हुआ। 01 नवंबर को उद्घाटन सत्र से शुरू हुए इस महोत्सव में तीन दिनों तक प्रबंधन, तकनीक, कला, संगीत और विधि से जुड़ी अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें ग्वालियर एवं बाहर के शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) दिवाकर सिंह राजपूत, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि सांस्कृतिक आयोजन शिक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और खेल जैसे सामाजिक विषयों पर तैयार की गई प्रस्तुतियों को सराहा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र भी हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. असित यादव, डीआईजी, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अनुशासन, कानून के सम्मान और सकारात्मक सोच का महत्व बताया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान को व्यवहार का हिस्सा बनाने की अपील की।

संस्थान के निदेशक प्रो. (डॉ.) निर्मल्य बंद्योपाध्याय ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि स्पंदन का चार दिवसीय सफर विद्यार्थियों की मेहनत और टीम भावना का परिणाम है। सांस्कृतिक संध्या की समन्वयक सहायक प्राध्यापक सुश्री स्वीटी दुबे तथा स्पंदन–2026 की समन्वयक सहायक प्राध्यापक सुश्री सोनम कुशवाह ने अतिथियों का स्वागत किया।



# जेयू के कुलगुरु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित

**-संतोष सिंह कुशवाह**

**जगत प्रवाह. ग्वालियर।** जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत को शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए ऑब्जर्वर पीस फाउंडेशन, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अमर बहादुर सिंह एवं ट्रस्टी प्रो. अमर ज्योति सिंह ने कुलगुरु को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके शैक्षणिक योगदान और शिक्षा के प्रति समर्पण की सराहना की। इस उपलब्धि पर जेयू के शिक्षकों, मित्रों एवं शिक्षाविदों ने कुलगुरु को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

# उत्तराखण्ड पुलिस को राष्ट्रपति निशान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षणः गृहमंत्री अमित साय

**-प्रमोद कुमार**

**जगत प्रवाह. देहरादून।** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिजर्व पुलिस लाइन, देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस निशान अलंकरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया तथा उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत किया। राज्य पुलिस बल की 25 वर्षों की सेवा, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान में प्रदान किया गया यह निशान उत्तराखण्ड पुलिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उत्तराखण्ड यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 16वां राज्य बन गया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक नारायण सिंह नफलच्याल एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक से पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र, सहायक सेनानायक श्रीमती प्रतिमा भट्ट एवं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक अभिसूचना सौहकार पुण्डीर को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस के विशेष डाक आवरण एवं पुलिस पत्रिका का विमोचन भी किया। अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान प्राप्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के प्रत्येक पुलिस अधिकारी और जवान के लिए गौरव का क्षण है। उत्तराखण्ड पुलिस ने अपने सेवा भाव, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और धार्मिक स्थलों के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुरक्षा तथा चारधाम यात्रा और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों की व्यवस्थाओं का सफल संचालन उत्तराखण्ड पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन पुलिस के जवान पूरी निष्ठा से कर रहे हैं।



# दीपा डोड़वे ने संभाला टिमरनी एसडीओपी का पदभार, कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई पर रहेंगी नजरें

**-प्रमोद बरसले**

**जगत प्रवाह. टिमरनी।** पुलिस विभाग में प्रशासनिक बदलाव के तहत डीएसपी दीपा डोड़वे ने टिमरनी एसडीओपी (अनुविभागीय अधिकारी पुलिस) का पदभार संभाल लिया है। उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियों का नया अध्याय शुरू हो गया है। अब टिमरनी अनुभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर नियंत्रण और आमजन की समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। टिमरनी अनुभाग में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। नए एसडीओपी के सामने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश, संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई तथा पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां रहेंगी। इसके साथ ही क्षेत्र में महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता और आम नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जैसे विषय भी पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

### आमजन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद

किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यशैली का आकलन केवल अपराधों पर कार्रवाई से ही नहीं, बल्कि आमजन के साथ व्यवहार, शिकायतों के निराकरण और पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास से भी किया जाता है। ऐसे में टिमरनी क्षेत्र के लोगों को उम्मीद रहेगी कि नए एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।

### चुनौतियों के बीच नई जिम्मेदारी

एसडीओपी का पद किसी भी पुलिस अनुविभाग में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद पर रहते हुए थाना प्रभारियों के कार्यों की निगरानी, अपराधों की समीक्षा, विवेचनाओं की प्रगति और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखना प्रमुख दायित्वों में शामिल होता है।

# आंदोलन के बदलते स्वरूप



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अक्टूबर माह देश के बड़े जनआंदोलनों के जनक नेताओं के स्मृति का माह माना जा सकता है। महात्मा गांधी ने तो समूचे देश को जाति, धर्म, धन और सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठाकर एकजुट किया और 19वीं सदी में दुनिया की तत्कालीन महाशक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को उपनिवेशों की आजादी के लिये लाचार किया था। महात्मा गांधी का आजादी का आंदोलन भारत की आजादी का भी था और दुनिया के उपनिवेशों के मन में आजादी की भूख को पल्लवित कर उन्हें आजादी के संघर्ष के लिये प्रेरित करने वाला भी था। लगभग सारी दुनिया के उपनिवेशों के लोगों ने महात्मा गांधी में उनके अहिंसा के विज्ञान और तरीकों में आजादी को देखा और इसलिये महात्मा गांधी समूची दुनिया में आजादी और नैतिक जीवन मूल्यों के सबसे बड़े मान्य शाश्वत प्रतीक है। डॉ. लोहिया ने जून 1946 में ही गोवा मुक्ति संग्राम की शुरुआत की थी। आजादी के बाद समूचे देश के गरीबों और आम लोगों को अहिंसक सिविल नाफरमानी के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह को आगे भी बढ़ाया और उस परंपरा को जीवित रखा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उनके समर्थक बौद्धिकों की यह राय थी कि आजादी के बाद अब देश में सत्याग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु लोहिया ने इस विचार का जोरदार खंडन किया और लोगों को समझाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार अहिंसक सिविल नाफरमानी है जो न केवल व्यवस्था के अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है, बल्कि व्यक्ति को निर्भय भी बनाता और आजादी को भी बचाता है। लोहिया ने आजादी और समता के लक्ष्य को एक साथ जोड़ा तथा सात क्रांतियों के रूप में बांधा था। 1974 में जेपी ने भी बिहार के छात्र आंदोलन की अगुवाई स्वीकार करते हुये उसे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के रूप में बदलने का प्रयास किया। उस दौर में शुरु हुये जनआंदोलन और राजनैतिक सत्ता आकांक्षाओं ने मिलकर इस आंदोलन में वैचारिक या राजनैतिक या अवसर की उम्मीद से सहभागिता की थी।

महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन और जेपी के आंदोलन में बड़ा फर्क था। गांधी का आंदोलन देश के जन-धन का आंदोलन था और जेपी का आंदोलन अराजनैतिक होने के उपदेश से शुरू होकर राजनैतिक दलों की सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा में बदल गया और अराजनैतिक से शुरू हुई यात्रा राजनैतिक दल के निर्माण यानि जनता पार्टी के निर्माण पर समाप्त हुई। इस आंदोलन का मौलिक रूप से कोई वैचारिक आधार नहीं था बल्कि यह एक गुजरात में महंगाई के मुद्दे से शुरू हुआ छात्र आंदोलन था जो बाद में वहां की सत्ता की दौड़ में पराजित राजनीति की सत्ता आकांक्षाओं का आंदोलन बन गया। जेपी के आंदोलन से भयभीत सरकार ने आपातकाल लगाया और फिर आपातकाल की मुक्ति के नाम पर एक ऐसा राजनैतिक दल उभरा जो विभिन्न प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का समूह था, तथा जो अपने जन्म से ही अपनी मृत्यु के लिये अभिसप्त था। इस आंदोलन और राजनैतिक दल की न कोई एक वैचारिक दृष्टि थी न ही कोई एक अंतरमन से स्वीकार्य नेतृत्व का केंद्र था। जनसंघ के मित्रों के लिये जेपी उतनी ही दूर तक स्वीकार थे जितनी दूर तक वे उनके आवरण में सत्ता हथिया सकते थे।

पिछले अप्रैल-मई के माह में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नीट पेपर लीक से पीड़ित छात्रों के लिये कटु और गैर जरूरी टिप्पणी जिसमें छात्रों को कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था कि प्रतिक्रिया भारत में कम हुई परंतु अमेरिका में अधिक हुई और अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बन गयी। बहुत लोगों की राय में यह स्वप्रेरित घटना नहीं थी बल्कि एक प्रायोजित प्रयोग था। पेपर लीक कांड और उसके बाद पुनरू परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम आने के बाद व लगभग ग्यारह लाख पचास हजार छात्रों के पास होने के बाद एक युवा साथी अमेरिका से भारत आये। उन्हें भारत सरकार ने जंतर मंतर



दिल्ली में आंदोलन करने के लिये लाल कालीन बिछा दिया। पुलिस को बगैर किसी आवेदन और बगैर स्वीकृति के जंतर मंतर पर उनकी सभा हुई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरे आदर सम्मान के साथ आंदोलन करने दिया और वे अगले जून माह की 20 तारीख को पुनरू आंदोलन की घोषणा कर अपने घर पूना चले गये। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिये उन्हें अपना घर छोड़कर अन्यत्र रहना पड़ रहा है। अब वे उन्हें लाकर अपने घर पर रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने उनसे बैठक की, मुख्यमंत्री ने उनसे हालचाल जाना, परंतु किसी ने भी उनसे धमकी देने वाले का नाम और नंबर नहीं पूछा, क्योंकि इस पूछताछ से झूठ बेपर्दा हो सकता था। मीडिया ने भी उनके माता-पिता की धमकी की खबर जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, परंतु किसी ने भी उनसे यह नहीं पूछा कि आखिर धमकी देने वाले कौन थे, ये घटनायें अपने आपसे काफी कुछ संकेत देती हैं? कारपोरेट और सत्ताधारी लॉबी उन्हें एक और केजरीवाल के रूप में खड़ा करना चाहती है। दुनिया के कारपोरेट से भारत के काफी स्वयंसेवी नाम के संगठन जीवन रस पाते हैं। उनमें दक्षिणपंथी भी हैं, वामपंथी भी हैं, कांग्रेसपंथी भी हैं और कुछ अन्य भी।

अमेरिका से भेजे गये छात्र नेता और उसके पीछे की रणनीति को ये वामपंथी संगठन भी बेहतर जानते हैं। जिनके लिये एक ही कुएं से पानी मिलता है, वे एक-दूसरे को बेहतर जानते हैं। प्रचार तंत्र के इस हमले के लाभ लेने के लिये वे भी सावधान थे तथा वामपंथी याने सीपीआई, सीपीएम, माले और एनजीओ के पुराने खिलाड़ी आम आदमी पार्टी के योद्धा देश के छितरे बितरे एनजीओ जो वर्षों से बेरोजगार थे, उन सभी को यहां संभावना नजर आई और वे सभी जंतर मंतर धरने में प्रवेश करा दिये गये। अत्रा हजारे का एक बार चेहरा चल चुका था, अतरू अब दूसरा सिक्का स्विटजरलैंड से सोनम वांगचुक को बुलाया गया।

खैर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 5-7 दिनों के खेल में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह भाषा गांधी-लोहिया-जेपी के आंदोलन की भाषा नहीं थी। जेन-जी के नाम से जो नौजवान युवक युवतियों की टोली आई थी, उनके नारों में कुछ एक तो सुनने और कहने लायक भी नहीं है, वैसी आजादी की कल्पना कोई सभ्य समाज तो नहीं कर सकता, हो सकता है कि उनके परिवारजन और माता-पिता भी उसे स्वीकार न कर सकें?

आजादी के आंदोलन में नारे आजादी और गांधी तक सीमित थे, लोहिया के आंदोलन में नारे कार्यक्रमों और लोहिया के थे। जेपी के आंदोलन में नारे कुछ मुददों और जेपी तक थे। पर इस तथाकथित जेन जी के आंदोलन में नारे न कार्यक्रमों के थे, न नीतियों के थे, बल्कि अधिकांश तो गंदी गालियों के थे।

दूसरे इस आंदोलन में छात्रों और धरना देने वाले समूहों और पुलिस के बीच कटुता व टकराव था। तथा आंदोलन में गांधी के अनुशासन की मान्यतायें नहीं थी। लगभग हर व्यक्ति और समूह अपनी पहचान और रील बनाने के लिये नये-नये अपशब्दों और गालियों को गढ़ रहा था। संख्या की दृष्टि से यह बहुत छोटा आंदोलन था जिसमें अंतिम चरण में यानि जून के आखिरी समय में कुछ हजार लोग थे, वे किसी सूत्र में बंधे नहीं थे बल्कि वे अपने-अपने प्रतीक चिन्हों और राजनैतिक पहचान को स्थापित करने में लगे थे। जिसमें कुछ अमेरिका से प्रायोजित छात्र समूह, कांग्रेस समर्थक, आम आदमी पार्टी, सपा के छात्र, एआईएसएफ और एआईएसए के वामपंथी, चन्द्रशेखर की भीम पार्टी कुछ अनुसूचित जाति के संगठन कुछ सवर्ण मानसिकता के आरक्षण विरोधी और यूजीसी नियमों को समाप्त करने की मांग करने वाले सब शामिल थे।

इस उन्मादी भीड़ ने न केवल पत्रकारों से बल्कि आंदोलन के समर्थक पत्रकारों से भी भारी अभद्रता की। एआई से बनाये गये चित्र और जुमले भी काफी चले ताकि देश में व छात्रों में एक उत्तेजना पैदा हो। अब दो दिनों से फिर जंतर मंतर पर एसआईआर के खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ है, हालांकि यह अभियान आरंभ से ही विभाजित है। इसकी शुरुआत वामपंथी और आम आदमी पार्टी ने की और अब एक भिन्न तिथि पर कांग्रेस समर्थक समूह आयोजन कर रहे हैं, उसके बाद कॉकरोच समूह ने घोषणा की है कि अपनी-अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार राजनैतिक दल, सामाजिक समूह, विदेशी धन प्राप्त एनजीओ, तथाकथित सेलीब्रेटी हीरो-हीराइन इनमें शामिल होकर मीडिया में छप रहे हैं और अपनी फिल्मी भूमिका निभा रहे हैं। परंतु जो यह नई शैली आंदोलन की विकसित हो रही है वह और उसकी भाषा न गांधीवादी है, न लोहियावादी और न ही जेपी वाली। बल्कि एक अराजक समाज और नारीवाद के नाम पर पुरुष और नारी के बीच एक विभाजक रेखा खींचने का एक विकृत प्रयोग है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऐसी घटनायें हुई हैं जिसने महिलाओं के मन में कुछ डर पैदा किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में एक निर्भया कांड, ममता बनर्जी के काल में एक आर्जीकर की घटना हुई थी और भाजपा के काल में बंगाल, बिहार, मप्र में महिलाओं के नाम पर अनेकों घटनायें हुई हैं। अगर कोई ऐसा कानून बन सकता हो कि इन बेटियों के खिलाफ जुर्म करने वालों को तत्काल मृत्युदंड दिया जा सकता हो तो उसे बनाया जाना चाहिये। परंतु हर पुरुष अपराधी है, यह कहना उचित नहीं है? क्या कुछ महिलाओं के द्वारा अपने पतियों की हत्या के लिये सारी महिलायें अपराधी हैं? मेरी राय में ये दोनों दृष्टिकोण गलत होंगे। जो समाज में, परिवारों में और घरों में मानसिक विभाजन रेखा खीचेंगे और संशय पैदा करेंगे। परिवार की टूटती संस्था पर एक और चोट करेंगे। कुछ बेटियों ने नारा लगाया कि एक कचौड़ी दो समोसा, मर्द जात का क्या भरोसा? क्या उन्हें अपने पिता, भाई पर से विश्वास टूट चुका है? अगर ऐसा है तो यह सोच देश को नष्ट करने वाली होगी।

मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ पुलिस के खिलाफ तथा महिला विरोधी व्यवहार के चित्र आये हैं, उनकी जांच और पुष्टि अभी होना है। पिछले जून माह में ऐसी कुछ घटनायें रील के माध्यम से प्रचारित की गई थी, परंतु उनकी भी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई। अब यह झूठ प्रचार तथाकथित जेन जी आंदोलन के लिये मुद्दा भी नहीं बचा।

अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी बेटी के साथ आपराधिक कृत्य किया है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिये परंतु यह भी आश्चर्यजनक है कि सैकड़ों महिला पुलिस तथा सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति में ऐसी घटना हो और लोग रील बनाये, परंतु उसका प्रतिकार न करें? क्या महिला पुलिस में एक भी ऐसी महिला नहीं थी? क्या आंदोलनकारियों में क्या कोई भी आंदोलनकारी नहीं था जो पुलिस अधिकारी से टकरा सकता था? जिसे उस बेटी में अपनी बेटी नजर आई हो। यह चिंता का विषय है। समूचे समाज को अब और राजनैतिक दलों को आंदोलन की नैतिकता और भाषा की सीमायें बांधना चाहिये तथा पुलिस को भी अपनी मानवीय मर्यादायें सीमांकित करनी चाहिये। भूलना नहीं है कि हम सैकड़ों साल विदेशी गुलामी में रहे हैं। क्योंकि हम जातियों में बंटे हुए थे। अब अगर पुरुष और नारी के भेद में इस प्रकार बंट जायेंगे तो क्या देश के सारे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पीछे नहीं छूट जायेंगे? तब परिवार में आपसी विश्वास नहीं होगा। तो क्या देश वास्तव में एक देश रह पायेगा?

हमें आज बहन सौफिया कुरैशी को आदर्श मानना होगा, वह धर्म, जाति से ऊपर उठकर अपने देश की सुरक्षा के लिये समर्पित और आदर्श हैं। उस भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स को आदर्श मानना होगा, जो आठ माह तक नासा अमेरिकी अंतरिक्ष में एक पुरुष सहकर्मी के साथ रही और दोनों ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के लिये अपने जीवन को दांव पर लगाया और नैतिक मूल्यों की सीमा रेखा को नहीं तोड़ा। हालांकि यह अमेरिकी समाज का प्रशंसनीय पक्ष है। ऐसे ही उदाहरणों से राष्ट्रीय एकता और देश मजबूत होता है। अगर हर नारी यह मानने लगे कि हर पुरुष अपराधी है तो इसका एक अर्थ यह भी है कि नारी को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। नारी को अपना आत्मविश्वास तथा साहस, बचाना होगा। नर-नारी की समानता, एक आदर्श लक्ष्य है, जिसमें कोई पक्ष न कमजोर होता है, न पूर्णतरू बुरा। अगर द्रोपती के चीरहरण के लिये, एक पुरुष दुर्योधन अपराधी था तो उसके सम्मान की रक्षा करने वाला एक और पुरुष कृष्ण भी तो था।

# दीपावली पर घर ही नहीं, जीवन भी रोशन हो

दीपों की रोशनी से दिशाएँ जगमगाती हैं,
प्रेम और विश्वास से ज़िंदगियाँ मुस्कुराती हैं।

दीपावली पर हम घरों की सफाई करते हैं, लेकिन क्या कभी मन में जमा अहंकार, रिश्तों में आई दूरियाँ और व्यवहार में बढ़ती कड़वाहट को साफ करने का विचार करते हैं? आज घर बड़े हो रहे हैं, लेकिन परिवार छोटे; संपर्क बढ़ रहे हैं, लेकिन संवाद घट रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों शुभकामनाएँ भेजने वाले हम, कभी अपने ही घर में बैठे व्यक्ति का हाल पूछना भूल जाते हैं। आर्थिक समृद्धि की दौड़ में भावनात्मक संपन्नता कहीं पीछे छूट रही है। ऐसे समय में दीपावली केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का अवसर है। क्यों न इस बार घर के साथ अपने विचार, व्यवहार और संबंधों को भी रोशन करें?

**आज की बात**



**प्रवीण कक्कड़**
स्वतंत्र लेखक



## दूरियाँ मिटाएँ, संवाद बढ़ाएँ और खुशियों मनाएँ

### परंपरा में छिपा जीवन का दर्शन

दीपावली भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की स्मृति से जुड़ी है। जैन परंपरा में भगवान महावीर का निर्वाण और सिख परंपरा में बंदी छोड़ दिवस भी इसी उत्सव से जुड़े हैं। इन परंपराओं का साझा संदेश है अंधकार पर प्रकाश और बंधन पर मुक्ति। धनतेरस स्वास्थ्य एवं समृद्धि, नरक चतुर्दशी बुराइयों से मुक्ति, दीपावली सुख-समृद्धि, गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और भाई दूज रिश्तों के स्नेह का संदेश देती है। इन पाँच दिनों में जीवन के पाँच आधार छिपे हैं - स्वास्थ्य, सदाचार, समृद्धि, प्रकृति और संबंध। इन्हें जीवन में उतारना ही उत्सव की सार्थकता है।

### घर के साथ मन की सफाई

धूल घर को मैला करती है, अहंकार संबंधों को। इस दीपावली किसी पुरानी नाराजगी को समाप्त कीजिए। जहाँ गलती हुई है, क्षमा माँगिए; जहाँ चोट पहुँची है, क्षमा कीजिए। याद रखिए, झुकने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, रिश्ते बड़े होते हैं।

### अपनों को उपहार नहीं, समय दीजिए

आज महंगे उपहारों की चमक में आत्मीयता खो रही है। माता-पिता के पास बैठिए, पुराने मित्र को फोन कीजिए, किसी नाराज रिश्तेदार से पहल करके मिलिए। उपहार की कीमत भुलाई जा सकती है, लेकिन अपनापन जीवनभर याद रहता है।

### परिवार में संवाद के दीप जलाइए

एक ही घर में रहकर भी मोबाइल की स्क्रीन हमें अलग-अलग संसारों में बाँट रही है। इस दीपावली कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहिए। बच्चों को सुनिए, बुजुर्गों के अनुभव जानिए। परिवार साथ रहने से नहीं, एक-दूसरे के लिए समय निकालने से मजबूत होता है।

### समृद्धि के साथ संतोष भी कमाइए

धन आवश्यक है, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। बड़ी उपलब्धियाँ भी अर्थहीन हैं, यदि उन्हें बाँटने वाले अपने ही दूर हो जाएँ। कमाई के साथ स्वास्थ्य, ईमानदारी, मानसिक शांति और संबंधों की पूँजी भी बढ़ाइए। यही वास्तविक लक्ष्मी है।

### किसी दूसरे की दीपावली भी रोशन कीजिए

त्योहार की खुशी केवल अपने घर तक सीमित क्यों रहे? किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, अकेले बुजुर्ग से मिलिए, कर्मचारियों के योगदान का सम्मान कीजिए। दान केवल धन का नहीं, समय, सम्मान और संवेदना का भी होता है।

### उत्सव मनाइए, जिम्मेदारी भी निभाइए

दिखावे की प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक खर्च से बचिए। स्थानीय कारीगरों से खरीदारी कीजिए, पर्यावरण का ध्यान रखिए। त्योहार ऐसा हो जिसमें अपनी खुशी के साथ पड़ोसी की शांति और समाज का हित भी सुरक्षित रहे।

### स्वयं को बदलने का संकल्प लीजिए

हर दीपावली नया सामान खरीदते हैं, इस बार कोई नई अच्छी आदत अपनाइए। क्रोध कम कीजिए, स्वास्थ्य सुधारिए, समय का सम्मान कीजिए। परिवर्तन की शुरुआत दूसरों से नहीं, स्वयं से कीजिए। यही आत्मप्रकाश है।

### प्रकाश का वास्तविक अर्थ

इस दीपावली यह मत गिनिए कि कितने दीप जलाए, यह देखिए कि कितनी दूरियाँ मिटाईं, कितने रिश्ते सँवारे और कितने चेहरों पर मुस्कान लाई। दीपक का उजाला रातभर रहता है, लेकिन अच्छे कर्मों और सुंदर व्यवहार का प्रकाश पीढ़ियों तक रहता है।

इस बार दीपावली केवल मनाइए मत, अपने जीवन और व्यवहार में उतारिए।

---

# हर साल की भांति इस बार भी दिल्ली में जहरीली हवा

**पर्यावरण की फिक्र**



**डॉ. प्रशांत सिन्हा**
पर्यावरणविद

दिल्ली की सुबह अब धुंध और खाँसी की आवाज से शुरू होती है। आसमान का नीला रंग धूल, धुआँ और जहरीली गैसों के परदे में छिप जाता है, जबकि बच्चे, बुजुर्ग और साँस के रोगी सबसे पहले इसका भार झेलते हैं। पूरी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचनांक 400 के पार है जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य, जीवन और भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट है। प्रत्येक सर्दी के आगमन के साथ सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों का नक्शा लाल रंग से भरने लगता है। यह लाल रंग केवल किसी नक्शे का रंग नहीं, बल्कि लाखों लोगों की साँसों में घुल रहे जहर का संकेत है। दिल्ली-एनसीआर इस समस्या का सबसे चर्चित केंद्र अवश्य है, परंतु यह संकट केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले लोग जहरीली हवा के प्रत्यक्ष शिकार बन रहे हैं। प्रदूषण अब केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं रहा; यह जनस्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भावी पीढ़ियों के अधिकारों से जुड़ा राष्ट्रीय संकट बन चुका है। समाचारों में आया था कि प्रदूषण से भारत में एक वर्ष में करीब 25 लाख लोगों की मृत्यु हुई। यह आँकड़ा चौंकाने वाला है, विशेष रूप से तब, जब हमारे कानून प्राकृतिक संसाधनों को संपत्ति के अधिकार के दायरे में रखते हैं, परंतु नागरिकों को स्वच्छ हवा पाने का प्रभावी अधिकार देने में अभी भी कमी है। वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में लगभग 95 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में जीवन बिता रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4.16 लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण से जुड़े कारणों से हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'एयर पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ' रिपोर्ट में भी कहा गया था कि वर्ष 2016 में दुनिया भर में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग छह लाख



बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई, जिनमें एक लाख से अधिक भारतीय बच्चे थे।

प्रदूषित हवा केवल खाँसी या साँस लेने में कठिनाई नहीं पैदा करती। यह नवजातों के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है। इससे बच्चों के मस्तिष्क और अन्य अंगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दमा, श्वसन संक्रमण, फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी, एलर्जी, जन्म के समय कम वजन और मानसिक विकास में बाधा जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। वयस्कों में भी हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियाँ और अन्य पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। हवा के प्रवाह में कमी, तापमान में गिरावट, वाहनों का धुआँ, निर्माण स्थलों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाना तथा पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने जैसी घटनाएँ मिलकर स्थिति को भयावह बना देती हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुँचा, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया।

सरकारें नीतियाँ बना रही हैं, नियम लागू कर रही हैं और निर्माण कार्यों पर रोक लगा रही हैं। फिर भी प्रदूषण का स्तर घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि वायु प्रदूषण किसी प्रशासनिक सीमा को नहीं मानता। यह एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रुके बहता है। इसलिए इसका समाधान केवल दिल्ली में प्रतिबंध लगाने से संभव नहीं; इसके लिए क्षेत्रीय, समन्वित और दीर्घकालिक नीति आवश्यक है। सरकार को कड़े कदम चाहिए। सरकार को अब केवल आपातकालीन उपायों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक प्रभावी क्षेत्रीय विनियामक ढाँचा बनाना होगा, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य एक साझा योजना पर काम करें। पराली के विकल्प, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन की सख्त निगरानी और प्रदूषण करने वालों पर त्वरित कार्रवाई इसके अनिवार्य हिस्से होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश, सरकारी तंत्र की सक्रियता, सम-विषम योजना और निर्माण पर रोक जैसे उपायों के बावजूद स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि समस्या केवल कानून की नहीं, बल्कि क्रियान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भी है। दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 के तहत वाहनों, निर्माण, डीजल जनरेटर और ईंधन के उपयोग पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, परंतु इन्हें केवल कागजी आदेश नहीं बनने देना होगा। प्रदूषण का दोष केवल सरकार पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। निजी वाहनों का अंधाधुंध उपयोग, कचरा जलाना, पटाखों का शौक, धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों की लापरवाही और पर्यावरण नियमों की अवहेलना- ये सब मिलकर हवा को जहरीला बनाते हैं। जनता को सार्वजनिक परिवहन अपनाना, कारपूलिंग करना, कचरे का उचित निपटान करना और खुले में जलाने से बचना होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और खुले में कचरा या बायोमास जलाने से बचने का आग्रह किया है। हमें यह समझना होगा कि स्वच्छ हवा कोई अनुदान नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यदि आज हम इस चेतावनी को हल्के में लेंगे, तो कल हमारे बच्चे साफ आसमान के बजाय मास्क और नेबुलाइजर के साथ बड़े होंगे। सरकार को नीतियों में दृढ़ता और जनता को व्यवहार में अनुशासन चाहिए। अन्यथा, भविष्य की पीढ़ियाँ हमसे यही पूछेंगी कि जब साँस लेने की हवा तक जहरीली हो गई, तब भी हमने क्यों नहीं जागा।

# सुशासन के संकल्प से

## नवा रायपुर बन रहा

# एजुकेशन हब

प्रबंधन | उद्यमिता | नवाचार

**NSTI**
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

**NIELIT**
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी

**NMIMS**
नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

**NIFT**
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी



**NFSU**
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कैम्पस

R.O. No. : 14133/ 1






श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

/ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर


स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक। RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)